Vol. 7, Issue 4, January 2018 ISSN 2249-894X

REVIEW OF RESEARCH

An International Multidisciplinary Peer Reviewed & Refereed Journal

Impact Factor: 5.2331

UGC Approved Journal No. 48514

Chief Editors
Dr. Ashok Yakkaldevi
Ecaterina Patrascu
Kamani Perera

Associate Editors
Dr. T. Manichander
Sanjeev Kumar Mishra

REVIEW OF RESEARCH
ISSN: 2249-894X
IMPACT FACTOR : 5.2331(UIF)
VOLUME - 7 | ISSUE - 4 | JANUARY - 2018

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र में सूचना केन्द्रः ग्रामीण समुदाय की आवश्यकता के संदर्भ में

डॉ. शालिनी शुक्ला
प्रभारी ग्रंथालय पं. सुन्दरलाल शर्मा(मुक्त) विश्वविद्यालय, छ.ग.बिलासपुर.

सारांश
प्रस्तुत शोध में छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सूचना केन्द्रों के विषय में सामान्य जानकारी एवं सुझाव प्रस्तुत किया गया है।छत्तीसगढ़ जैसे पिछड़े क्षेत्र में विकास के साथ–साथ छत्तीसगढ़ राज्य की विकास संबंधी नीतियों तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ–साथ जागरूक बनाने

के लिये जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका है। सूचना, प्रसारण तथा फिल्म के क्षेत्र में विकास का दायित्व सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय का है। केन्द्र शासन की जनसंचार नीति के अंतर्गत समाचार पत्रों पर प्रेस परिषद् के माध्यम से अंकुश लगाना। केन्द्र शासन की आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिये फिल्म, रेडियो तथा दूरदर्शन के माध्यम से जनसंख्या को जोड़ना।

ग्रामीण श्रोताओं के लिये कृषि एवं गृह कार्यक्रम प्रतिदिन प्रसारण करना। ये कार्यक्रम कृषि के तरिकों, मौसम की रिपोर्ट, ग्रामीण विकास योजनाओं, महिला और बाल विकास पर आधारित होतें है। ग्रामीण कार्यक्रमों में पर्यावरण संरक्षण, महिला समृद्धि योजना, राष्ट्रीय सामाजिक सहायता और एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, जवाहर रोजगार योजना, पंचायती राज, जल संभरण प्रबंध आदि कार्यक्रमों पर बल दिया जाता है। आकाशवाणी के कई केन्द्रों से यूनिसेफ (United Nation's Childrens's Emergency Fund) और राज्य सरकार के सहयोग से मां और शिशु की देखभाल पर श्रृंखला का प्रसारण प्रारंभ किया गया है।

कृषि एवं गृह कार्यक्रमों के 40 प्रतिशत कार्यक्रम ग्रामोन्मुखी होते है और केवल खेतों–खलिहानों और गांव में ही रिकार्ड किये जाते है। भारत सरकार का सूचना और प्रसारण मंत्रालय 2 अक्टूबर 1995 से 5 फरवरी 1996 तक चार अलग–अलग चरणों में चलाया, जिसमें देश के 135 आकाशवाणी केन्द्रों ने हिस्सा लिया। इस अभियान के लिये खासतौर पर 6207 कार्यक्रम तैयार किये गये थे। आकाशवाणी के कृषि एवं गृह एकांश से संबंधित ग्रामीण कार्यक्रम सलाहकार समितियां, कृषि एवं गृह कार्यक्रमों की योजना बनाने की प्रक्रिया से जुड़े हुए है।

परिचय–पूरे विश्व में जनसंख्या तीव्रतर दर से वृद्धि हो रही है जिसमें हमारा देश जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे क्रम में आता है। जबकि चीन का स्थान प्रथम है। जनसंख्या वृद्धि के साथ ही मनुष्य की दैनिक आवश्यकताएं जैसे खाद्य, वस्त्र एवं रहने के लिए स्थान आदि पर तीव्र प्रभाव पड़ता है। और इनकी पूर्ति के लिए जो साधन होते हैं, जनसंख्या वृद्धि के कारण वे इन आवश्यकताओं की पूर्ति करने में असफल हो जाते हैं और इसके लिए अप्राकृतिक वस्तुओं की आवश्यकता होती है। जनसंख्या में वृद्धि के कारण सूचना की आवश्यकता होतीहै ग्रामीण समाज को किस प्रकार की सूचना अवश्यकता होती है एवं वह अपनी आवश्यकता के अनुरूप सूचना प्राप्ति की पूर्ति किस माध्यम से करता है। ग्रामीण को सूचना की प्राप्ति अन्य इलेक्ट्रानिक संचार माध्यम जैसे – दूरदर्शन, रेडियों, चलचित्र एवं समाचार पत्र आदि से होती है। ग्रामीण समुदाय अपनी सूचना आवश्यकता की पूर्ति हेतु अनौपचारिक स्त्रोत पर ही आश्रित है, ग्रामीण ग्रंथालय के संबंध में उनको जानकारी नहीं के बारबर है। ग्रामीणों को अपनी व्यवसाय जैसे कृषि, लधु उघोग संबंधी एवं अन्य सूचना की प्राप्ति की आवश्यकता महसूस होती है जिसकी पूर्ति वह रेडियों व टी.वी के माध्यम से ही सूचना प्राप्ति को पसंद करते है। इलेक्ट्रनिक माध्यम से अपने पसंद के कार्यक्रम जैसे कृषि दर्शन, आगनवाड़ी, क्षेत्रीय कार्यक्रम आदि के माध्यम से

जानकारी एकत्रित करते है। कुछ ग्रामीण पढ़े लिखे है वह समाचार पत्र के माध्यम से सूचना प्राप्त करते है, समाचार पत्र को या तो अपने घर में मंगाते है अथवा वहां आस–पास की दुकानों पर जाकर समाचार पत्र पढ़कर सूचना की पूर्ति करते हैं।

शोध का उददेश्य–

1. ग्रामीण समुदाय की आधारभूत सूचना आवश्यकता को जानना।
2. ग्रामीण समुदाय की सूचना संतुष्टि का पता लगाना।
3. ग्रामीण सूचना सेवा के विभिन्न माध्यमों का पता लगाना।
4. ग्रामीणों में सूचना केन्द्रों के प्रति जागरूकता उत्पन्न कराना।
5. ग्रामवासियों के लिए चलाई गई योजनाओं में अधिकतम उपयोगी योजनाओं का पता लगाना।
6. ग्रामीणों के विभिन्न सूचनाओं में से अधिकतम सूचना आवष्यकता हेतु लगाव को जानना।

शोध समंक संग्रहण की प्रविधि – प्रस्तुत शोध में आकडों का एकत्रित करनें में निम्न निम्न विधियों का उपयोग किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायत, नगरीय प्रशासन (नगर पंचायत/नगर पालिक/नगर निगम) के ग्रंथालय एवं सामुदायिक सूचना केन्दों के माध्यम से।

शोधका क्षेत्र –प्रस्तुत शोध छत्तीसगढ़ राज्य के विभिन्न ग्राम पंचायत, नगरीय प्रशासन (नगर पंचायत/नगर पालिक/नगर निगम) के ग्रंथालय एवं सामुदायिक सूचना केन्दों को सम्मिलित किया गया है।

छत्तीसगढ़ राज्य के ग्रामीण समुदाय के उद्योग धंधे–

छत्तीसगढ़ राज्य में कोरिया, जशपुर, सरगुजा, रायगढ़, कोरबा, कांकेर, बस्तर, दंतेवाड़ा, राजनांदगांव, कबीरधाम वाले आजादी के पूर्व देशी रियासते थी।

वर्तमान में सरगुजा जिले के तहसील उदयपुर भी एक छोटी रियासत थी तथ उसका स्वतंत्र अस्तित्व था। रियासत के जमाने में लोगों की सामान्य जरूरतों के अनुसार उनका व्यवसाय भी सामान्य था। पनिका जाति के लोगों का मुख्य व्यवसाय उद्योग था। ये गहने और मोटा कपड़ा बुनने का कार्य करते थे।

भरेखा तथा कसेर जाति के लोग पीतल के बर्तन, ईट और मकान के कवेलू बनाते थे। लोहार खेती के लिए नगर तथा घरों में काम आने वाले लोहे के औजार बनाते थें। अनुसूचित जाति के लोग (चमार) जूता तथा पानी खींचने के मोट तथा हल के जोत आदि बनाते थे। रियासत में ग्रामीण उद्योग के नाम पर कोई विशेष वस्तुओं का निर्माण व उत्पादन नहीं किया जाता था। वर्तमान जशपुर जिला भी आजादी के पूर्व एक देशी रियासत थी। जशपुर जिला आदिवासी बहुल जिला है।

रघुवीर प्रसाद की पुस्तक ''झारखण्ड झंकार'' में जशपुर के बारे में लिखा गया हैंः– ''राज्य का मुख्य व्यवसाय कपड़ा बुनना है जो कि चिक जाति के लोगों के हाथ में है। प्रायः लोग सूत कांटकर चिकों के पास ले जाते और वे कपड़ा बुनते है। उरांव और कोल जाति के लोग जब तक उनके सूत का कपड़ा न बुन जाये तब तक चिक के घर में डेरा डाल देते है। अधिकतर गमछा, धोती आदि ही बुनी जाती है। चिक लोग बाहर की सूत खरीदकर कपड़ा बुनते और बेचते है।''

प्रचीन छत्तीसगढ़ ने सरगुजा जिला भी एक बड़ी देशी रियासत थी। उद्योग धंधों के क्षेत्र में जिला अभी भी पिछड़ा हुआ हैं चूंकि सरगुजा जिला भी एक आदिवासी बहुल जिला है। जाहिर है कि आदिवासी जनसंख्या आज भी अपनी पुरानी रूढ़िवादी तथा पंरपरावादी तरिकों से जीवनयापन करते है। आजादी के पूर्व सरगुजा जिला भी एक अत्यन्त पिछड़ा क्षेत्र था।

व्यवसाय तथा उद्योग के क्षेत्र में यहां प्रचुर साधनों के होने के बावजूद भी वह जिला अभी भी सुप्त अवस्था में है। यहां की प्राकृतिक निधि असीम है पर यातायात मार्ग की न्यूनता के कारण अभी भी इस प्रदेश में प्राकृतिक साधनों का उपयोग नहीं हो पाता है।

मुख्य व्यवसाय कृषि हैं नगरों में कृषि से ही संबंधित कुछ उद्योग धंधें जैसे चावल, गेहूं आदि की मिले है। यहां की विशेष व्यापार वन्य उत्पादनों का है। वन से यहां लकड़ी, कपड़ा, खैर, चीड़ के पत्ते तथा हर्रा आदि प्राप्त किये जाते है। लकड़ी की मिलें जिले के सभी नगरों में हैं। गांव के चारागाहों की सुविधा के कारण पशुपालन मुख्य उद्योग है। गांव के लोग कृषि एवं पशुपालन में संलग्न है। कृषि तथा पशुपालन के साथ घरेलू उपयोग की वस्तुए स्वयं तैयार करते है।

कपड़ा बुनना यहां की पनिका जाति का जातिगत व्यवसाय है।

कपड़ा बनाने का कोई मिल नहीं है। सीतापुर तथा पटना आदि स्थानों में कपड़ा बुनने का काम अभी होता है। गांव में मिट्टी के बर्तन कुम्हार जाति के लोग बनाते है जो छोटी मात्रा में तैयार किये जाते है। लारिया जाति के लोग बांस के टोकरे व अन्य छोटी–मोटी चीजे बनाते है। गांव में बढ़ई भी काफी संख्या में है। चर्मकार लोग चमड़े का काम करते है। तिलहन से तेल निकालने का काम हर गांव में होता है।

लोहार जाति के लोग कृषि के औजार बनाते है। यह कार्य पूरे क्षेत्र में होता है। सरगुजा में लोहारों की जाति को ''अधरिया'' कहते है जो इस कार्य में दक्ष होते है। तांबे तथा पीतल के बर्तन आदि भी तैयार किये जाते है।

1951 की जनगणना के अनुसार सरगुजा जिले में (1961) पारिवारिक उद्योग ;भ्वनेमीवसक प्दकनेजतलद्ध में 17,976 कामगारों को रोजगार उपलब्ध था जबकि मेन्युफेक्चरिंग में (फैक्ट्री) में 2181 व्यक्तियों को रोजगार प्राप्त है।

1971 की जिले की ग्रामीण उद्योग धंधों में कुछ परिवर्तन दिखाई देता है। पारिवारिकउद्योग धंधों में 10,381 व्यक्तियों तथा फैक्ट्री में 3154 व्यक्तियों को रोजगार दिया जाता है।

छत्तीगढ़ राज्य में स्वामित्व अनुसार स्थापित लघु उद्योग

क्रं.	जिला	स्थापित लघु उद्योग				
		कुल	सामान्य वर्ग	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अ.जा. एवं ज.जाकी इकाईयों का प्रतिशत
1	2	3	4	5	6	7
1.	रायपुर	307	209	49	49	31.92
2.	महासमुंद	19	19	0	0	0
3.	धमतरी	44	32	1	11	27.27
4.	दुर्ग	38	36	2	0	5.26
5.	राजनांदगाव	42	40	1	1	4.78
6.	कवर्धा	25	23	2	0	8
7.	बस्तर	50	42	3	5	16
8.	उत्तर बस्तर	25	17	2	6	32
9.	दक्षिण बस्तर	4	4	0	0	0
10	बिलासपुर	325	236	67	22	27.38
11.	जांजगीर–चांपा	130	118	10	2	9.23
12.	कोरबा	9	9	0	0	0
13.	स्रगुजा	28	28	0	0	0
14.	कोरिया	74	64	5	5	13.51
15	रायगढ़	73	53	12	8	27.39
16.	जशपुर	207	111	44	52	76.37
योग		**1400**	**1041**	**198**	**161**	**25.64**
प्रतिशत–		**100.0**	**74.35**	**14.14**	**11.90**	

स्त्रोत– संचनालय, वाणिज्य एवं उद्योग, छत्तीसगढ़ 2010–11

तालिका में अवलोकन से पता चलता है कि सबसे अधिक 325 लघु उद्योग की स्थापना बिलासपुर जिले में की गई। राजधानी रायपुर दूसरे स्थान पर है। राज्य शासन की ओर से अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वर्ग के छोटे–छाटे उद्योगों को प्रोत्साहित करने के कारण 198 तथा 161 लघु इकाईयां स्थापित की गइ। कुछ जिले जैसे महासमुंद, दक्षिण बस्तर, कोरबा, सरगुजा जिला में 2010–11 की जानकारी के अनुसार अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के लोगों द्वारा एक भी लघु उद्योग स्थापित नहीं किये जा सकें।

छततीसगढ़ में वर्ष 2010–11 में कुल 1400 लघु इकाईयों में 74.35 प्रतिशत समान्य वर्ग 14.14 प्रतिशत

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति द्वारा लघु उद्योगों की स्थापना की गई थी।

स्वामित्य के आधार पर लघु उद्योगों में पूजी निवेश की स्थिति

क्रं.	जिला	स्थापित लघु उद्योग में पूजी निवेश			
		कुल	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	प्रति उद्योग में पूंजी निवेश
1	2	3	4	5	6
1	रायपुर	714.08	33.44	6.97	2.33
2	महासमुंद	229.65	0	0	12.09
3	धमतरी	134.73	0.2	0	3.06
4	दुर्ग	629.5	13.74	0	16.57
5	राजनांदगाव	293.58	2.1	0.02	6.99
6	कवर्धा	15.2	1	0	0.61
7	बस्तर	532.35	0.49	18.92	10.65
8	उत्तर बस्तर	59.92	0.49	14.95	2.26
9	दक्षिण बस्तर	33.22	0	0	8.31
10	बिलासपुर	538.1	6.53	3.06	1.66
11	जांजगीर–चांपा	18.4	1.58	0.12	1.42
12	कोरबा	61.96	0	0	6.88
13	सरगुजा	118.84	0	0	4.24
14	कोरिया	301.13	0.21	0.15	4.07
15	रायगढ़	763.68	0.99	0.38	10.46
16.	जशपुर	63.6	2.21	3.88	0.31
योग		**4673.38**	**86.77**	**51.07**	**3.34**

स्त्रोत– संचनालय, वाणिज्य एवं उद्योग, छत्तीसगढ़ 2010–11

तालिका में छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिलों में स्थापित लघु उद्योगों में सबसे अधिक 763.68 लाख रूपये की पूंजी का दूसरे क्रम 714.08 लाख रूप्ये तथा तीसरे क्रम में दुर्ग जिले में 629.50 लाख रूपये का पूंजी का निवेश किया गया।

कवर्धा जिले में सबसे कम 15–20 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। इसके बाद जांजगीर–चांपा में 18.40 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित 1400 लघु उद्योगों में कुल 4673.38 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। अनुसूचित जाति द्वारा 86.77 लाख रूपये तथा अनुसूचित जनजाति द्वारा सबसे कम 51.07 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया।तालिका 3.2 में छत्तीसगढ़ के सभी 16 जिलों में स्थापित लघु उद्योगों

में सबसे अधिक 763.68 लाख रूपये की पूंजी का दूसरे क्रम 714.08 लाख रूप्ये तथा तीसरे क्रम में दुर्ग जिले में 629.50 लाख रूपये का पूंजी का निवेश किया गया।

कवर्धा जिले में सबसे कम 15–20 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। इसके बाद जांजगीर–चांपा में 18.40 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। इस प्रकार छत्तीसगढ़ राज्य में स्थापित 1400 लघु उद्योगों में कुल 4673.38 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया। अनुसूचित जाति द्वारा 86.77 लाख रूपये तथा अनुसूचित जनजाति द्वारा सबसे कम 51.07 लाख रूपये का पूंजी निवेश किया गया।

सुझाव–

केन्द्र सरकार ही राष्ट्रीय नीति का निर्धारण करती है और राज्य उसका अनुसरण करता है किन्तु राष्ट्र एवं राज्य विशेष की सबसे छोटी इकाई आम ग्रामीण जो ग्राम में बसता है उन नीतियों से मिलने वाले लाभ से 30 प्रतिशत तक ही लाभन्वित हो पाता है, इसका प्रमुख कारण सूचना तन्त्र की श्रृखलाबद्ध ढंग से संचालन न होना व इसकी संपूर्ण जानकारी ग्रामीणों को न होना है। ऐसे में ग्राम केन्द्र की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण कड़ी साबित होगी, गांव में कृषि के आलावा लधु उद्योग, पशुपालन, कुटीर उद्योग संचालित है, उन सभी के लिए शासन समय–समय पर योजना का निर्माण करती है, इसके अतिरिक्त पानी, बिजली, भोजन, चिकित्सा, मकान, कर्ज, जीवन बीमा जैसी सुविधाएं ही शासन की नीतियों का निर्धारण करती है। इन सबके लिए सबसे पहले उन्हीं ग्राम ज्ञान केन्द्र तक पहुचना, उसकी महत्ता बताना, उसका लाभ उठाना भी उन्हें बताना होगा।

उपसंहार –

में छ.ग. राज्य के ग्रामीण क्षेत्र के सूचना केन्द्रों का अध्ययन किया गया है। छ.ग. जैसे पिछड़े क्षेत्र में विकास के साथ–साथ छ.ग. राज्य को विकास संबंधी नीतियों तथा स्वस्थ मनोरंजन प्रदान करने के साथ–साथ जागरूक बनाने के लिए जनसंचार की महत्वपूर्ण भूमिका सूचना प्रसारण मंत्रालय की है। केन्द्र शासन की संचार नीति के अंतर्गत समाचार पत्रों पर प्रेस परिषद के माध्यम से अंकुश लगाना, केन्द्र शासन की आर्थिक, सामाजिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों के लिए फिल्म, रेडियों, तथा दूरदर्शन के माध्यम से जनसंख्या को जोड़ना।

अध्ययन में लघु उद्योगों के विकास के सभी पक्षों अध्ययन किया गया है, जैसे – उद्योगों के प्रकार, क्षमता, उत्पादन, निर्यात, रोजगार तथा पूंजी निवेश आदि से संबंधित सूचना का संग्रह करता है और उनको यह प्रक्रियाबद्ध कर प्रसारित करता है। यह अध्याय मुख्यतः तीन बिन्दु पर आधारित है – ग्रामीण समाज को सूचना आवश्यकता, ग्रामीण जनता के उद्योग एवं ग्रामीण समाज में सूचना का प्रतिफल।

संदर्भ ग्रंथ :

1. भारत 1996, प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली अगस्त 1997 पृ. 258
2. भारत 1970 प्रकाशन विभाग, सूचना तथा प्रसारण मंत्रालय भारत सरकार, नई दिल्ली 1970 पृ. 123
3. रघुवीर प्रसाद, झारखण्ड झंकार बनारस 1930 पृ. 39
4. वही. पृ. 56
5. वही. पृ. 113, 122
6. सरगुजा जिला गजेटियर, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. भोपाल 18 जुलाई 1989 पृ. 108
7. रायगढ़ जिला गजेटियर, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. भोपाल 18 जुलाई 1976 पृ. 138
8. वही. पृ. 139
9. बिलासपुर जिला गजेटियर, गजेटियर संचालनालय, संस्कृति विभाग, म.प्र. भोपाल 18 जुलाई 1978 पृ. 184
10. ग्रामोद्योग विभाग छ.ग. शासन छत्तीसगढ़ सेवाद का प्रकाशन अक्टूबर 2007 (ब्रोचर)
11. नई डगर–नए शिखर–छत्तीसगढ़ का कायाकल्प जनसंपर्क संचालनालय छ.ग. शासन रायपुर 2006 राज्योत्सव पृ. 46
12. त्रिपाठी एम.एस. संदर्भ एवं सूचना सेवा के नवीन माध्यम वाई के पब्लिकेशन आगरा 1993 पृ. 415–419
13. कार्यक्रम अधिकारी, ग्रामीण विकास सेल, आकाशवाणी केन्द्र, रायपुर 2009
14. भारत 2007, प्रकाशन विभाग, सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली पृ.668
15. छततीसगढ़ स्थापना दिवस 1 नवंबर 2000,जनसंपर्क विभाग का प्रकाशन पृ. 5,6

16. भारत 2007 पृ. 7,8
17. नहीं, पृ. 224
18. छत्तीसगढ़ राज्य के जिला स्तरीय सामाजिक आर्थिक विकास संकेतक 2005, आर्थिक एवं सांख्यकीय संचालनालय, रायपुर पृ. 43,55,60,61,63
19. स्कूल शिक्षा विकास सबका छ.ग. शासन, जनसंपर्क संचालनालय राज्योत्सव 2006 पृ. 3,4
20. छत्तीसगढ़ शासन, आर्थिक सर्वेक्षण 2006–07, आर्थिक एवं सांख्यकीय संचालनालय रायपुर छ.ग. पृ. 113
21. वही. पृ. 115
22. वही. पृ. 106